

D. E. 1 ed 2nd form

6 May 2020
Wednesday

Present Indian Society and
Elementary Education

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

स्वतंत्र भारत में शिक्षा के समग्र रूप पर विचार को धारी 'समिति' (1964-66) में किया। जिसके आधार पर जुलाई 1968 में केंद्रीय भारत की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' की घोषणा की गयी, किन्तु शिक्षा नीति के प्रस्तावों को पूर्णरूपेण लागू नहीं किया जा सका।

जनवरी 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सत्ता सम्भालते ही नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करने एवं लागू करने की घोषणा की। जिससे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गयी। इस समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर 'Challenge of Education - A Policy Perspective' डायग्नोसिक प्रकाशित किया गया।

इस डायग्नोसिक के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित प्रारूप को अन्तिम प्रारूप प्रदान करने के लिए 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल (CABE)' के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और मई, सन् 1986 ई० में संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी। और स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अभिप्राय: ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है, जिसके अन्तर्गत जाति, धर्म, लिंग एवं निवास के भेदभाव के बिना एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मकता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश के 'शैक्षिक विकास' में गीत का फल है। 1990 में आचार्य रामसूक्ति की अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी समीक्षा की। इसकी सिफारिशों पर शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड (सलाहकार) ने विचार किया आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन. लक्ष्मीन रेड्डी की अध्यक्षता में 22 जनवरी, 1992 को नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट का सुझाव दिया। सलाहकार बोर्ड जिसके परिष्कार स्वरूप 'जुलाई 1992' को शिक्षा के केन्द्रीय रबी रखी गयी। 19 अगस्त 1992 को संशोधित नीतियों कुछ सुझाव के साथ समक्ष रखी गयी। सभी के लिये प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये पाँच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गयी ताकि समुदाय की

आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को बनाया जा सके।

तथा आर्थिक दृवीकरण और उद्गारीकरण की
नयी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

B.R.C. Dooband
Amis Bro - Sapn 9
Tyage